मैन्यूफैक्चरिंग में मजबूती के बगैर निर्यात में रफ्तार नहीं

चीनी अर्थव्यवस्था भी निर्यात आधारित है और मैन्यूफैक्चरिंग इसे एक मजबूत आधार देती है। इसलिए निर्यात के जरिये विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए मजबूत मैन्यूफैक्चरिंग नीति की भी जरूरत है

निर्यात के आंकड़े एक बार फिर निराशाजनक रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार मार्च में निर्यात 5.7 फीसदी गिर कर 28.7 अरब डॉलर का ही रह गया। ऐसे हालात में जब चालू खाते का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है तो निर्यात में यह गिरावट और चिंता पैदा करती है। निर्यात में यह गिरावट बाजार वैश्विक बाजार में छाई सुस्ती की वजह से है। यूरो जोन की हालत डांवाडोल है। स्पेन में भारी मंदी है। इटली की हालत भी खस्ता है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में रिकवरी की रफ्तार बेहद धीमी है और इस वजह से उपभोक्ता मांग नहीं बढ़ रही है। ऐसे हालात में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में इजाफा हो भी तो कैसे?

हालांकि वित्त वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारित 20 फीसदी निर्यात लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। लेकिन मार्च में इस गिरावट का पहले से ही अंदाजा था। यूरोप की हालत लगातार कमजोर चल रही है और यह भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। इटली, स्पेन, पुर्तगाल और आयरलैंड जैसे देशों में सरकार के कटौती पैकेज की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है। सार्वजनिक खर्चे कम हुए हैं और लोगों के वेतन, भत्तों में भारी कटौती हुई है। जाहिर है इससे लोगों की क्रयशक्ति में भारी गिरावट हुई है और इसका असर भारतीय निर्यात पर पड़ा है। निर्यात में यह गिरावट ज्यादा स्थायी नहीं भी हो सकती है। लेकिन भारत के लिए यह ज्यादा चिंता की बात इसलिए है कि इस समय भुगतान संतुलन नकारात्मक जोन में चला गया है। दिसंबर से डॉलर के प्रवाह में कमी आई है और तीन महीने के दौरान भुगतान संतुलन की स्थिति खासी बिगड़ गई है।

दिसंबर तिमाही में चालू खाते का घाटा बढ़ कर 19.6 अरब डॉलर का हो गया है। यह पिछले साल के 9.7 अरब डॉलर की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा है। तेल आयात के बढ़े हुए बिल और सोने के आयात से चालू खाते के घाटे पर और ज्यादा नकारात्मक असर हुआ है। हालात नहीं सुधरे तो चालू खाते का बढ़ता घाटा रुपये को और कमजोर कर देगा। वित्त वर्ष 2011 में डॉलर की तुलना में 11 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। विदेशी निवेश में कमी और नीति-निर्माण के मोर्चे पर ठोस फैसला न ले पाने की वजह से नए निवेश में गिरावट भी रुपये की कमजोरी की एक बड़ी वजह रही है। इस बीच मार्च महीने के दौरान आयात में 24.3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। आयात के आंकड़ों को देखें तो पता चलेगा कि बिल में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी पेट्रोलियम, सोना, चांदी और कोयले की रही है। लेकिन सरकार पेट्रोलियम सब्सिडी पर कोई ठोस फैसला नहीं ले पा रही है। डीजल, कुकिंग गैस और केरोसिन में सब्सिडी जारी है। सब्सिडी वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने का काम भी नहीं हो पा रहा है। दरअसल सब्सिडी का बहुत बड़ा हिस्सा उन लोगों को मिल रहा है, जिन्हें इसकी जरूरत नहीं है। बहरहाल देश में मैक्रोइकोनॉमी के दूसरे मोर्चों पर बेहतर प्रदर्शन के बगैर निर्यात के मोर्चे पर बहुत बड़ी सफलता हासिल करना मुश्किल होगा। निर्यात बढ़ाने के लिए मैन्यूफैक्चरिंग में एक बड़ी ताकत बनने की जरूरत है। चीनी अर्थव्यवस्था भी निर्यात आधारित है और मैन्यूफैक्चरिंग इसे एक मजबूत आधार देती है। इसलिए निर्यात के जरिये विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए मजबूत मैन्यूफैक्चरिंग नीति की जरूरत है।